भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

विषयः भारत का विदेशी ऋणः प्रास्थिति रिपोर्ट, अगस्त, 2006

1. आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर भारत के विदेशी ऋण के संबंध में प्रास्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जिसमें वर्ष के दौरान भारत के विदेशी ऋण में हुए घटनाक्रमों पर प्रकाश डाला जाता है। आज जारी की गई बारहवीं प्रास्थिति रिपोर्ट में मार्च, 1990 से मार्च, 2006 तक के आंकड़े उपलब्ध कराने के अतिरिक्त वर्ष 2005-06 के दौरान देश के विदेशी ऋण से संबंधित घटनाक्रमों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत के विदेशी ऋण/ऋण संकेतकों की अन्य ऋणी देशों के साथ तुलना भी की गई है।

2. भारत के विदेशी ऋण का स्टाक मार्च-अंत 2005 के 123.2 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर मार्च-अंत 2006 में 125.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। वर्ष 2004-05 में 11.6 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि की तुलना में 2005-06 में वृद्धि लगभग 2 बिलियन अमरीकी डालर थी। वर्ष 2005-06 में विदेशी ऋण के संचय का अपेक्षाकृत कम स्तर मुख्यतया दिसंबर, 2005 में 5.5 बिलियन अमरीकी डालर के इंडिया मिलेनियम डिपाजिट (आईएमडी) के उन्मोचन के कारण हुआ था। संघटक-वार 2005-06 के दौरान ऋण स्टाक में वृद्धि मुख्यतया एनआरआई जमाराशियों में बढ़ोत्तरी और अल्पावधिक ऋणों में उछाल के कारण हुई थी जिन्हें अंशतः वाणिज्यिक उधारों और द्विपक्षीय ऋणों में कमी द्वारा प्रति संतुलित कर दिया गया था।

3. गत कुछ वर्षों में ऋण की मात्रा में वृद्धि होने के बावजूद विदेशी ऋण के संकेतकों में निरन्तर सुधार हुआ है। विदेशी ऋण-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 1991-92 के 38.7 प्रतिशत से क्रमिक रूप से गिरता हुआ 2005-06 में 15.8 प्रतिशत पर आ गया। चालू प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ऋण शोधन (ऋण सेवा अनुपात) पिछले वर्षों में गिरता हुआ 2005-06 में 6.1 प्रतिशत के स्तर पर (आईएमडी के तहत वापसी अदायगियों के एकल लेन-देन को छोड़कर) पहुंच गया। इसी प्रकार, कुल ऋण में अल्पावधिक ऋण तथा विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों के संदर्भ में अल्पावधिक ऋण की स्थिति में क्रमिक सुधार देखा गया है। सुधार आरंभ होने से बाद की अवधि में ऋण संचय में सन्तुलन और ऋण वहनीयता के संकेतकों में सुधार मुख्यतया विदेशी ऋण को नियंत्रणीय सीमाओं में रखने के सरकार के प्रतिबद्ध प्रयासों को प्रतिबिम्बित करता है।

4. भारत के विदेशी ऋण की स्थिति अन्य ऋणी देशों से बेहतर है। भारत के विदेशी ऋण के संकेतक जैसे कि कुल ऋण में अल्पावधिक ऋण का अनुपात और विदेशी मुद्रा भण्डार के प्रति अल्पावधिक ऋण का अनुपात शीर्ष दस ऋणी देशों में सबसे कम है। कुल ऋण में रियायती ऋणों का अनुपात सबसे अधिक है, जबकि ऋणं और सकल राष्ट्रीय आय तथा ऋण शोधन अनुपात वर्ष 2004 में सबसे कम अनुपात की श्रेणी में चीन के बाद दूसरे स्थान पर थे। विश्व के शीर्ष दस ऋणी देशों में भारत ने 1991 में तीसरे स्थान से अपनी स्थिति सुधार कर 2004 में आठवॉ स्थान ग्रहण किया है।

5. सम्पूर्ण रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की वेबसाइट- http://www.finmin.nic.in पर उपलब्ध है।

एफ सं. 1(15)/2006-ईडीएमयू
नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2006

पत्र सूचना कार्यालय से उपर्युक्त विज्ञप्ति को जारी करने का अनुरोध किया जाता है।

आर. सी. श्रीनिवासन

(आर.सी. श्रीनिवासन)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

श्री बी.एस. चौहान,
निदेशक
जन सूचना अधिकारी
वित्त मंत्रालय
नार्थ ब्लाक